

बिना नंबर की स्कूल बस पर अब तक कार्रवाई नहीं, परिवहन विभाग की कार्यशैली कटघरे में

समय जगत, खिरकिया। नगर के हरदा रोड पर बिना स्पष्ट नंबर प्लेट के संचालित होती दिखाई दी सूर्योदय ग्लोबल एकेडमी की स्कूल बस को लेकर सामने आई खबर के बाद जिला परिवहन विभाग ने कार्रवाई का भरोसा तो दिया, लेकिन अब तक मौके पर जांच या किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सवाल केवल स्कूल बस की नंबर प्लेट तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। स्कूल बस में रोजाना मासूम विद्यार्थी सफर करते हैं। ऐसे में वाहन की पहचान, पंजीयन,

फिटनेस, परमिट, बीमा और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच बेहद महत्वपूर्ण है। बावजूद इसके, सड़क पर बिना स्पष्ट नंबर प्लेट दिखाई देने वाली बस का मामला सामने आने के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तो यह अभिभावकों की चिंता बढ़ाने वाला विषय है।

खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी ने दिया था कार्रवाई का भरोसा: मामला सामने आने के बाद जब जिला परिवहन अधिकारी राकेश अहाके से इस संबंध में जानकारी ली गई थी, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही कार्रवाई

हरदा रोड पर सूर्योदय ग्लोबल एकेडमी की बस का मामला

की जाएगी। अधिकारी के इस बयान के बाद उम्मीद थी कि परिवहन विभाग की टीम स्कूल बस की जांच करेगी और नियमों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं होने से सवाल उठ रहा है कि आखिर अधिकारी के संज्ञान में मामला आने के बावजूद जांच कब होगी?

क्या सिर्फ कागजों में हो रही स्कूल बसों की जांच?: खिरकिया नगर में कई स्कूलों की बसें और अन्य वाहन



प्रतिदिन बच्चों को लेकर सड़कों पर दौड़ते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या परिवहन विभाग द्वारा इन वाहनों की नियमित जांच वास्तव में की जा रही है या फिर जांच की प्रक्रिया केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित है? स्कूल बसों की जांच के दौरान वाहन का पंजीयन नंबर, फिटनेस प्रमाण-पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, चालक का लाइसेंस तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच होना जरूरी है। यदि किसी वाहन में

नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी अपेक्षित है।

फोटो सामने आई, अधिकारी के संज्ञान में मामला आया, फिर कार्रवाई क्यों नहीं?: इस पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल यही है कि जब बस की तस्वीर सार्वजनिक रूप से सामने आई, मामला जिम्मेदार अधिकारी के संज्ञान में आया और अधिकारी ने स्वयं जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया, तो फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

सुलगते सवाल: क्या विभाग ने बस की मौके पर जांच की? क्या बस के पंजीयन और फिटनेस की जांच की गई?

क्या वाहन के दस्तावेज वैध पाए गए? क्या स्कूल प्रबंधन से इस संबंध में जवाब मांगा गया? क्या बस पर नंबर प्लेट नियमानुसार लगाई गई है?

इनका कहना है

हरदा ने पूर्व में कहा था, आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी के संज्ञान में मामला आने और कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस मामले में परिवहन विभाग कब जांच करेगा और कब स्थिति स्पष्ट करेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

राकेश अहाके, जिला परिवहन अधिकारी

सार-समाचार

3000 किलो महुआ लाहन नष्ट, 30 बल्क लीटर हाथ मट्टी महुआ शराब जब्त, 5 प्रकरण दर्ज



समय जगत, पांडुरना। जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और विक्रय के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ के निर्देशन एवं सहायक आबकारी आयुक्त बी.आर. वेध के

मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने बुधवार को बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। आबकारी वृत्त पांडुरना के अंतर्गत ग्राम पीपलपानी, कोंदर एवं नीलकंठ में अवैध शराब निर्माण के अड्डों पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान नालों एवं जंगल में झाड़ियों के आसपास पत्तियों और इमों में हाथ भट्टी महुआ शराब बनाने के लिए एकत्रित करीब 3000 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया। आबकारी विभाग ने महुआ लाहन का नियमानुसार सैपल लेने के बाद शेष लाहन को निर्मूल्य होने के कारण मौके पर ही विधिवत नष्ट कर दिया। वहीं, कार्रवाई के दौरान 30 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ मदिरा जब्त कर विभाग ने अपने कब्जे में ली। इस कार्रवाई के संबंध में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(1)(च) के तहत कुल 5 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए हैं। संयुक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी भारती गौड़, वासुदेवाचार्य त्रिपाठी एवं राजेश सिंघल, आबकारी उपनिरीक्षक नरेंद्र नागेश, वृत्त प्रभारी अनिकेत पटेल सहित आबकारी विभाग का अमला मौजूद रहा। विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफकार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।

नेशनल लोक अदालत के प्रचार वाहन को प्रधान जिला न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना



मुरैना। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 12 सितम्बर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन तथा आमजन को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के त्वरित एवं आपसी सहमति से निराकरण की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से बुधवार को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरैना श्रीमती संगीता मदन ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन के माध्यम से जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ सुदूर अंचलों में नेशनल लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। वाहन के माध्यम से आमजन को नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया, लोक अदालत के लाभ तथा आपसी सहमति से विवादों के समाधान के संबंध में जानकारी दी जाएगी। साथ ही, अधिक से अधिक पात्र पक्षकारों को आगामी 12 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों के निराकरण हेतु सहभागिता के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर मुरैना मुख्यालय के न्यायाधीशगण, अभिभाषक संघ मुरैना के अध्यक्ष हरिसिंह सिकरवार, अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

डायल-112 की तत्परता से सड़क हदसे में घायल व्यक्ति को समय पर मिला उपचार

मुरैना। जिले में आमजन की सुरक्षा एवं त्वरित सहायता के लिए संचालित डायल-112 सेवा ने एक बार फिर तत्परता का परिचय दिया। माताबसैया थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112 भोपाल को घटना की सूचना प्राप्त होते ही माताबसैया थाना क्षेत्र में तैनात एफआरवी वाहन को तत्काल सहायता के लिए रवाना किया गया। डायल-112 स्टॉप ने मौके पर पहुंचकर देखा कि मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल पड़ा था। डायल-112 के जवानों ने बिना समय गंवाए घायल व्यक्ति को एफआरवी वाहन में बैठाया और तत्काल अस्पताल पहुंचाकर भर्ती कराया।

कालाबाजारी के लिए दिल्ली ले जाए जा रहे 90 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जप्त, दो आरोपी गिरफ्तार



मुर्ना। जिले में राशन सामग्री एवं घरेलू उत्पादों की कालाबाजारी तथा आवश्यक वस्तुओं की अवैध बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बागचीनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक लोडिंग वाहन से बड़ी मात्रा में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक लोडिंग वाहन में बड़ी संख्या में एलपीजी गैस सिलेंडर भरकर कालाबाजारी के

उद्देश्य से दिल्ली ले जाए जा रहे हैं। सूचना पर बागचीनी पुलिस ने तत्काल चेकिंग लगाकर लोडिंग वाहन को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन में इंडेन कंपनी के 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले 90 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर पाए गए। इन सिलेंडरों के संबंध में वैध लाइसेंस एवं दस्तावेज मांगे जाने पर आरोपी प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने सिलेंडरों सहित लोडिंग वाहन को जब्त कर लिया। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 14 लाख रुपये बताई गई है। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना बागचीनी में अपराध क्रमांक 194/2026, धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 287 एलपीजी के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मुर्ना धर्मराज मीना के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र पाल डावर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी जौरा नितिन बघेल के निदेशन में थाना बागचीनी पुलिस द्वारा की गई। कार्रवाई में थाना प्रभारी उमेश सिंह यादव सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

प्रभावित लोगों को दिए जा रहे मुआवजे की ली जानकारी

कलेक्टर ने कोयला उत्पादन, उत्खनन एवं परिवहन कार्यों की समीक्षा की

शहडोल। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिले में एसईसीएल द्वारा किए जा रहे कोयला उत्पादन, उत्खनन एवं परिवहन कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कोयला उत्खनन में अपनाई जा



रही आधुनिक तकनीकों, कोयले की गुणवत्ता, खदानों की स्थिति, उत्खनन क्षेत्रों तथा खनन से प्रभावित लोगों को दिए जा रहे मुआवजे सहित विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की। समीक्षा के दौरान एसईसीएल के जनरल मैनेजर ऑपरेशन मनीष कुमार श्रीवास्तव ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिले में संचालित कोयला खदानों तथा उत्पादन एवं उत्खनन कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अंडरग्राउंड एवं ओपन कास्ट माइंस सहित कुल 7 कोयला खदानें संचालित हैं। इन खदानों में कोयला उत्पादन को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इनमें सम्पोजे माइनिंग, कटीनस माइनिंग तथा हाईवॉल माइनिंग तकनीक प्रमुख हैं।

उन्होंने बताया कि जिले में संचालित खदानों में रामपुर बटुड़ा कोल माइंस सबसे नई

गुणवत्ता एवं उत्पादन की स्थिति के साथ ही कोयला परिवहन व्यवस्था की भी जानकारी ली। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजेश्वर अमृता गर्ग,

कोयला खदान है। कलेक्टर ने खदानों में अपनाई जा रही तकनीक, कोयले की

जिला खनिज अधिकारी राहुल शांडिल्य सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

अवैध खनिज परिवहन पर खनिज विभाग की कार्रवाई, दो वाहन जब्त

शहडोल। जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत खनिज विभाग के अमले ने बुढ़ार तहसील क्षेत्र में वाहनों की जांच कर अवैध रूप से खनिज परिवहन करते पाए



गए दो वाहनों को जब्त किया। जिला खनिज अधिकारी राहुल शांडिल्य ने बताया कि विभागीय अमले द्वारा बुढ़ार तहसील क्षेत्र में औचक निरीक्षण कर खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान एक वाहन में गिट्टी तथा दूसरे वाहन में कोयला खनिज का अवैध परिवहन पाया गया। दोनों वाहनों को तत्काल जब्त कर थाना बुढ़ार की

अभिरक्षा में खड़ा कराया गया है। मामले में खनिज नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रखने की बात कही गई है। कार्रवाई में सहायक खनिज अधिकारी अभिषेक पटेल सहित खनिज विभाग का मैदानी अमला शामिल रहा।

18 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म: मुरैना पुलिस की मानवीय पहल से दरभंगा के परिवार को मिला बिछड़ा सदस्य



मुरैना। खाकी का मानवीय चेहरा और कर्तव्यनिष्ठा का अनुपम उदाहरण पेश करते हुए जिला मुरैना के थाना देवगढ़ पुलिस ने एक बिछड़े हुए परिवार को 18 साल बाद पुनर्मिलन की अद्वितीय खुशी दी है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वर्षों से लापता बिहार निवासी एक व्यक्ति को पुलिस ने सकुशल

उसके चरिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्राप्त विवरण के अनुसार, बिहार के दरभंगा जिले के सिरनिया गाँव का निवासी यह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण लगभग 18 वर्ष पूर्व अपने घर से भटक गया था। वर्षों की अनवरत तलाश के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो परिजनों की उम्मीदें धुंधली

पड़ने लगी थीं। हाल ही में थाना देवगढ़ पुलिस को यह व्यक्ति मिला, जिसके बाद पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए इसके परिजनों की खोजबीन शुरू की और सफलता हासिल की। थाना परिसर में जब 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद परिजनों ने अपने बिछड़े हुए सदस्य को देखा, तो माहौल अत्यंत भावुक हो गया। चेहरे पर अपनों को वापस पाने की बेपनाह खुशी और आँखों में राहत के आँसू लिए परिजनों ने देवगढ़ पुलिस का सहृदय आभार व्यक्त किया। देवगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस का कार्य केवल अपराधों पर अंकुश लगाना ही नहीं, बल्कि जरूरत के समय असहाय लोगों का संबल बनना और बिछड़े अपनों को उनके परिवार तक पहुँचाना भी हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। आज एक परिवार को मुस्कुराता देख जो संतुष्टि मिली है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती।

गोपन के उपयोग पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी

गोटमार मेले की तैयारियों को लेकर शांति समिति की बैठक

समय जगत, पांडुरना। पांडुरना की ऐतिहासिक एवं गौरवशाली परंपरा गोटमार मेले के शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित आयोजन को लेकर बुधवार को शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन, पार्किंग सहित नागरिक सुविधाओं को लेकर प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र परिहार, अतिरिक्त कलेक्टर ज्योति ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद, संयुक्त कलेक्टर नेहा सोनी, एसडीएम पांडुरना अलका एक्का, विधायक निलेश उर्के, भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप मोहोड़, नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े सहित संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं पत्रकार मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर एवं पुलिस प्रशासन ने अधिकारियों को मेले से संबंधित सभी व्यवस्थाएं समयपूर्व



पूर्ण करने तथा आपसी समन्वय के साथ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रशासन का उद्देश्य गोटमार मेले की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखते हुए आयोजन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संभव कराना है।

गोपन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध, उत्खनन पर होगी कार्रवाई: गोटमार मेले के दौरान गोपन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध के बावजूद गोपन का उपयोग करते पाए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन एवं पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेशों का प्रभावी पालन

सुनिश्चित कराया जाएगा। मेले के दौरान सुबह 8 बजे से मेला समाप्ति तक पुलिस एवं प्रशासन की सतत निगरानी रहेगी। सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या कानून-व्यवस्था से जुड़ी स्थिति सामने आने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

यातायात और पार्किंग की रहेगी विशेष व्यवस्था: मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं नागरिकों की सुविधा को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। शहर में उपलब्ध खाली

स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। वहीं बड़े वाहनों को आवश्यकता पड़ने पर शहर के बाहरी क्षेत्रों में निर्धारित स्थानों पर पार्क कराया जाएगा। प्रवेश और निकासी मार्गों के साथ भीड़ प्रबंधन को लेकर भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।

मेले के दौरान यातायात एवं भीड़ प्रबंधन को थाने में रखते हुए शुक्रवार को आयोजित होने वाले साप्ताहिक बाजार को इस बार मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। संबंधित विभागों को बाजार व्यवस्था को लेकर आवश्यक समन्वय एवं तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।



संपादकीय

देश की आर्थिक विकास दर ने बढ़ाई उम्मीद

वैश्विक स्तर पर जारी उथल पुथल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था गतिशील बनी हुई है। दिनांक 31 अगस्त को सांयकाल में केंद्र सरकार ने भारत के वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के आंकड़े जारी किए हैं। विश्व बैंक एवं अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अन्य वैश्विक संस्थानों, एसोचेम, भारतीय रिजर्व बैंक आदि के अनुमानों को धत्ता बताते हुए अप्रैल-3 - जून 2026 की तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। जबकि, उक्त संस्थानों ने उक्त अवधि में 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। रूस-यूक्रेन युद्ध तो बहुत लम्बे समय से चल रहा है, ईरान-अमेरिका/ इजराईल युद्ध भी इस तिमाही में जारी रहा, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली थी। एक समय तो कच्चे तेल की कीमतें 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गई थीं। ज्ञातव्य हो कि भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है। ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने के पश्चात इस मार्ग से गुजरने वाले तेल के जहाजों को रोक दिया गया था एवं कच्चे तेल की आपूर्ति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा था। परंतु भारत ने इस दयनीय स्थिति को बहुत ही सुझ बूझ के साथ सम्भाला और अन्य कई देशों से तेल एवं गैस का आयात जारी रखा, जिससे भारत में न तो तेल की आपूर्ति कम हुई और न ही भारत में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। जबकि अन्य कई देशों में तो पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है। सकल मूल्य संवर्धन में वृद्धि दर 8.2 प्रतिशत की रही है जो अप्रैल-जून 2025 की तिमाही में 7 प्रतिशत की रही थी। विनिर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर पिछले वर्ष की तिमाही में 8.3 प्रतिशत की रही थी जो इस वर्ष की तिमाही में बढ़कर 9.2 प्रतिशत की हो गई है। इसी प्रकार सेवा के क्षेत्र में भी आर्थिक विकास दर इस वर्ष की प्रथम तिमाही में बढ़कर 10 प्रतिशत पर पहुंच गई जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 8 प्रतिशत रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था उपभोग आधारित है, अतः निजी उपभोग में इस वर्ष की तिमाही में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 6.8 प्रतिशत रही थी। वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में सराहनीय विकास दर हासिल करने को केंद्र सरकार की योजनाओं की सफलता के रूप में भी देखा जा सकता है तथा यह देश की आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से सकारात्मक संकेत है।

राष्ट्रीय एकता परिषद की सक्रियता है जरूरी

राजीव सचान

इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी विकास दर 7.8 प्रतिशत रहने पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जब यह कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद यह वृद्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और आर्थिक आत्मविश्वास का परिणाम है तो कांग्रेस को यह बिल्कुल रास नहीं आया। उसने अर्थव्यवस्था की तमाम कमजोरियों का उल्लेख करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। ऐसा नहीं है कि आर्थिक मोर्चे पर किसी तरह की समस्याएं नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस का उद्देश्य उन्हें गिनाना नहीं, बल्कि यह सिद्ध करना था कि जीडीपी में वृद्धि किसी तरह की उपलब्धि नहीं है। उसने यह काम पूरी शिद्दत से किया और इसके लिए कई प्रवक्ताओं को मैदान में उतारा। निःसंदेह किसी को यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि विपक्ष सरकार की प्रशंसा करेगा। विपक्ष का काम सरकार की खामियों को इंगित करना और उसकी गलतियों के लिए उसे कठवरे में खड़ा करना है। इससे ही सरकारों पर दबाव बनता है और वे सही तरह काम करने के लिए बाध्य होती हैं, लेकिन पिछले लगभग दो दशकों से असहमति की राजनीति अपनी हदों को पार कर विरोध के लिए विरोध की राजनीति में बदल चुकी है। विरोध के लिए विरोध की राजनीति के चलते आज राजनीतिक माहौल इतना कटुतापूर्ण, छिद्रान्वेधी और नकारात्मक हो गया है कि यदि कोई नेता ऐसा कुछ कह दे तो निरम्यों का मालन करे और संघम्य एवं अनुशासन का परिचय दे तो विरोधी दल के नेता इसका भी विरोध करने के लिए आगे आ सकते हैं। इसके लिए उनके पास तरह-तरह के (कु) तर्क भी होंगे। कटु एवं नकारात्मक राजनीतिक विमर्श का अक्सर सामाजिक विमर्श पर भी पड़ रहा है।

यह एक तथ्य है कि सोशल मीडिया कहे जाने वाले डिजिटल प्लेटफार्मों पर विचार-विमर्श का स्थान गाली-गलौज ने ले लिया है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक दलों के आडटी सेल विरोधी दलों के नेताओं पर प्रायः बिलो द बेल्ट यानी अपमानजनक प्रहार करते ही रहते हैं। अब ऐसे प्रहार करने के लिए एआइ का भी सहारा लिया जा रहा है। कई बार इसकी चपेट में महिला नेता भी आ जाती हैं। इसके नतीजे में राजनीतिक और सामाजिक माहौल बुरी तरह दूषित हो रहा है। इस प्रदूषण के दूर होने की कोई सूरत नहीं दिखती। कटुतापूर्ण राजनीति ने महापुरुषों की भी बांट दिया है। अब राजनीति और समाज के स्तर पर लोग किसी राष्ट्रीय दायित्व या अभियान के प्रति कटिनाई से ही एकमत और एकजुट होते दिखते हैं, जबकि देश की कई समस्याएं ऐसी हैं, जिन्हें लोगों की सामूहिक भागीदारी से ही दूर किया जा सकता है, जैसे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी से मुक्ति। आज स्वच्छ भारत जैसे अभियान असरहीन होते दिख रहे हैं तो इसीलिए कि इस अभियान में आम जनता की पहली जैसी भागीदारी नहीं दिखती। जब यह अभियान शुरू हुआ था तो आम लोगों की इसमें दिलचस्पी और भागीदारी दिख रही थी कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैले, लेकिन अब वह दिखाई नहीं देती। यह एक ऐसा अभियान है, जो आम जनता की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। यदि लोग सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से रोकने के लिए सक्रिय-सचेत नहीं रहते तो सरकारें और उनकी एजेंसियां कुछ भी कर दें, बात बनने वाली नहीं है। विडंबना यह है कि जब से यह अभियान शुरू हुआ, तबसे शायद ही किसी विपक्षी नेता ने इसे सफल बनाने में अपने लोगों को भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया हो। कुछ ऐसी ही स्थिति बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों की भी है। विरोधी राजनीतिक दलों को लगता है कि जिस दल ने इन अभियानों को शुरू किया, उनके लोगों को ही इनमें भागीदार बनने की आवश्यकता है। शायद यही कारण है कि हर घर लिंगा जैसे अभियानों में भी सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी नहीं दिखती। इसमें गहन संदेह है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विरोधी राजनीतिक दल किसी तरह का उन्साह-उमंग दिखाते होंगे। हैरानी नहीं कि मोदी सरकार के हटते ही इस दिवस को मनाना ही बंद कर दिया जाए।

यह एक तथ्य है कि जनभागीदारी वाले कई सामाजिक अभियान महज मोदी सरकार के अभियान बनकर रह गए हैं, जब स्थिति तब है, जब देश में कई समस्याएं ऐसी हैं, जिनका समाधान जनता की सामूहिक भागीदारी से ही किया जा सकता है। संकट यह है कि अब राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे पर एकमत नहीं होते-न तो संसद में और न ही संसद के बाहर। हालांकि इसके लिए राष्ट्रीय एकता परिषद के रूप में एक मंच है, लेकिन वह लंबे समय से निष्क्रिय है। यह सही समय है कि इस निष्क्रिय मंच को सक्रिय किया जाए। राष्ट्रीय एकता परिषद एक गैर-संवैधानिक निकाय है। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में सभी मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के नेता, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष, उद्योग, व्यापार, मीडिया और श्रमिक संघों के प्रतिनिधि होते हैं। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। कहीं यह मंच इसीलिए तो निष्क्रिय नहीं कि इसकी स्थापना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी? जो भी हो, यह ध्यान रखें कि इस परिषद का उद्देश्य सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और संकीर्णता जैसी समस्याओं का सामना करना था।

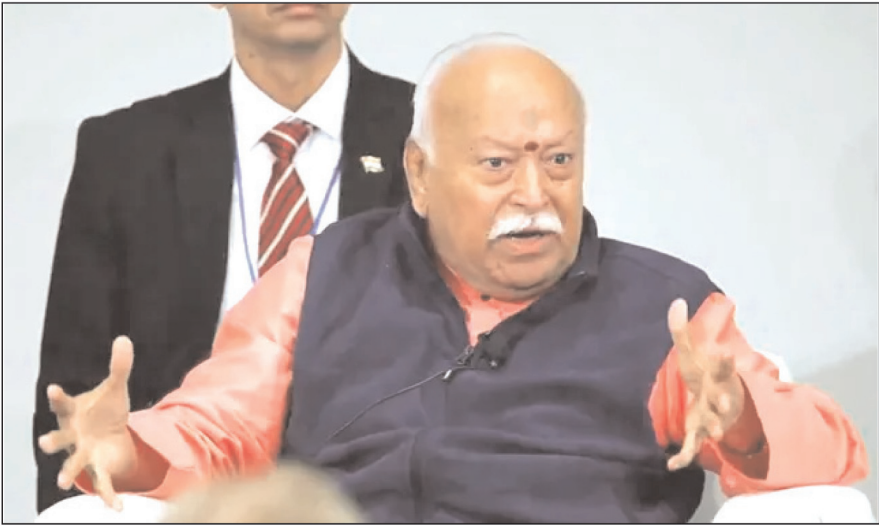
न्यूयॉर्क में मोहन भागवत ने दिया वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश

नजरिया

भागवत का संदेश अमेरिका में भारतीय मूल की नई पीढ़ी के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। पहली पीढ़ी के प्रवासी प्रायः भारत से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, जबकि दूसरी और तीसरी पीढ़ी अमेरिकी सामाजिक परिवेश में पली-बढ़ी है। उनके सामने प्रश्न रहता है कि वे अपनी भारतीय सांस्कृतिक पहचान को अमेरिकी नागरिकता के साथ किस प्रकार संतुलित करें।

डॉ. प्रवीण दाताराम

विश्व में अमेरिका अब एक सर्वाधिक विविधता भरा समाज बन गया है। अमेरीका को सौजन्यशाली विविधता देने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। अमेरिका में बसे अनेक प्रकार के भारतीय समुदाय आज अमेरिकी समाज को एक इंद्रधनुष का रूप देते हैं। यह हमारे लिए गौरान्वित करने वाला विषय है। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का भाषण सुनकर अमेरिका की एक प्रचलित कहावत स्मरण हो आई है 'प्लूरिबस यूनम' अर्थात् 'अनेक से एक'। भागवत जी ने अनेक ऐसे बिंदु चिह्नित किए जहाँ, वसुधैव कुटुम्बकम और अमेरिकी ई प्लूरिबस यूनम परस्पर पूरक और पर्याय सिद्ध होते हैं। सबसे बड़ी बात, उनका संदेश केवल अमेरिका में बसे भारतीयों के लिए नहीं था; उसमें भारत, भारतीयता, विविधता, सह-अस्तित्व और विश्व-मानवता के प्रति एक व्यापक दृष्टि का विकास क्रम था। भागवत जी ने अपने प्रबोधन में विविधता की भारत की शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि भारत की एकता विविधताओं से सजती है और विविधता में केवल परस्पर एडजस्ट करना पर्याप्त नहीं है, विविधता को स्वीकार कर उसे सम्मान और संरक्षण भी देना होगा। यही भारतीय दर्शन है। धार्मिक, नस्लीय और सांस्कृतिक ध्स्वीकरण के चक्र फँसे वर्तमान विश्व हेतु यही आवश्यक है। हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर स्पष्ट वक्तव्य था। उन्होंने दो टुक उस सोच को नकारा कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समाज को साझा पूर्वजों से जोड़ते हुए सेम डीएनए की बात भी दोहराई। भारतीय-अमेरिकी समुदाय आज अमेरिका के सर्वाधिक सफल और प्रभावी प्रवासी समुदाय में से एक है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और अनेक भाषाई-सांस्कृतिक समूह शामिल हैं। यदि भारतीय मूल के लोग अपनी भारतीय पहचान को किसी एक धार्मिक पहचान तक सीमित न करके एक साझा सभ्यतागत पहचान के रूप में देखते हैं, तो अमेरिकी समाज में भारतीय समुदाय की एकता और



प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। भागवत का संदेश अमेरिका में भारतीय मूल की नई पीढ़ी के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। पहली पीढ़ी के प्रवासी प्रायः भारत से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, जबकि दूसरी और तीसरी पीढ़ी अमेरिकी सामाजिक परिवेश में पली-बढ़ी है। उनके सामने प्रश्न रहता है कि वे अपनी भारतीय सांस्कृतिक पहचान को अमेरिकी नागरिकता के साथ किस प्रकार संतुलित करें। भागवत का दृष्टिकोण इस प्रश्न का सकारात्मक उत्तर देता है, अमेरिका के प्रति पूर्ण निष्ठा और भारत की सभ्यतागत विरासत के प्रति सम्मान एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। 'अपनी कर्मभूमि के प्रति निष्ठावान रहो' विदेशी भूमि पर जाकर अनेकों से यह कहने का सामर्थ्य, साहस और सहजता एक स्वयंसेवक या 'संघ विचार' के पास ही हो सकती है। यह विचार भारतीय-अमेरिकी समुदाय को हैफेंटेड एडिन्टिटी की समस्या से मुक्ति देकर एक आत्मविश्वासी नागरिक की पहचान देता है। मोहन भागवत जी के कहे पर चलें तो अमेरिकी भारतीय युवा श्रेष्ठ अमेरिकी होते हुए भी अपनी भारतीय जड़ों पर गर्व कर सकते हैं। भागवतजी ने भारतीयता को केवल धार्मिक आग्रह के रूप में नहीं बल्कि साझा

सांस्कृतिक और मानवीय विरासत के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। विश्व में अमेरिका अब एक सर्वाधिक विविधता भरा समाज बन गया है। अमेरीका को सौजन्यशाली विविधता देने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। अमेरिका में बसे अनेक प्रकार के भारतीय समुदाय आज अमेरिकी समाज को एक इंद्रधनुष का रूप देते हैं। यह हमारे लिए गौरान्वित करने वाला विषय है। भारतीय-अमेरिकी समुदाय अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तकनीक, चिकित्सा, शिक्षा, उद्यमिता और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यदि इस समुदाय में सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सामाजिक समरसता बढ़ती है तो उसका लाभ अमेरिकी समाज को भी मिलेगा।

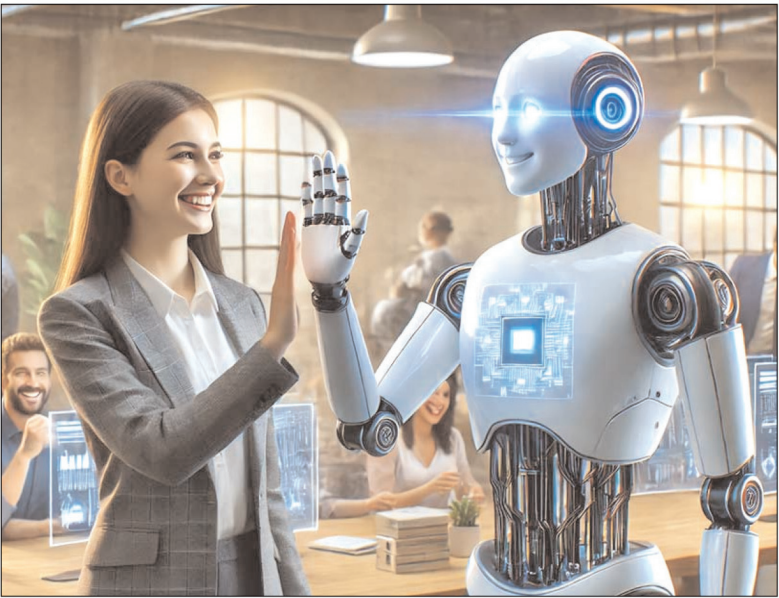
संघ प्रमुख ने भारतीय संस्कृति के प्रत्येक के रूप में तीन शब्द कहे एसेटेंस, रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्सन। उनके भाषण से यह पुनः सिद्ध हुआ कि 'सहिष्णुता' टोलरेंस भारतीय शब्द है ही नहीं। भारतीयता का मूल स्वर है स्वीकार्यता। 'सहिष्णुता' 'टोलरेंस से तो अहमू व्यक्त होता है। 'सहिष्णुता' शब्द से स्वर आता है कि तुम मुझे पसंद नहीं किंतु फिर भी तुम यहाँ रह लो । एसेटेंस और रिस्पेक्ट का अर्थ है, सभी

संवेदनशील शासन तंत्र से पूरी होंगी लोगों की अपेक्षाएं

डॉ. मनिष दाभाडे

आज भारतीय राजनीति में जेन-जी को लेकर जो हलचल दिख रही है, वह कोई अचानक उभरा हुआ रझान नहीं है। यह एक बड़े बदलाव की स्वीकृति है। सवाल यह है कि क्या यह पीढ़ी वाकई राजनीति में इतनी अहम है या फिर मीडिया के एक हिस्से और इंटरनेट मीडिया की चढ़न है? सच्चाई इन दोनों के बीच है। बड़ा-छाकर पेश करने वाली बात यह है कि हर चुनौती विश्लेषण अब जेन-जी को किसी जादुई ताकत की तरह पेश करने की जल्दी में है। वह भी तब जब हमारे चुनाव अब भी बहुत हद तक स्थानीय मुद्दों, जातिगत समीकरणों, सरकारी योजनाओं और नेताओं की छवि से ही तय होते हैं। भारत की करीब एक चौथाई आबादी जेन-जी है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के बावजूद राजनीतिक फैसलों के केंद्र में अपेक्षित स्थान नहीं पा रही। यही असंतुलन इसे अहम बना देता है। जब कोई इतना बड़ा तबका संस्थाओं के भीतर अपनी बात कहने की जगह नहीं पाता, तो वह स्वाभाविक रूप से संस्थाओं के बाहर अपनी आवाज ढूंढ़ने लगता है। जेन-जी की प्रकृति और स्वरूप पर विचार करें तो यह कोई एक जैसा एकरूप समूह नहीं है। यह इलाके, भाषा, जाति, वर्ग और आर्थिक हैसियत के हिसाब से बहुत अलग-अलग है। इसे वोट बैंक कहना उसकी असली तस्वीर को छेढ़ा करके देkhना होगा। बेंगलुरु के किसी स्टार्टअप में काम करने वाला युवक, प्रयागराज में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही छात्रा और किसी छोटे शहर में पारिवारिक काम-धंधा सभाल रहा लड़का, सभी जेन-जी के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनकी पसंद और प्राथमिकताएं भिन्नता लिए हो सकती हैं। इस पीढ़ी को किसी एक विचारधारा या किसी एक पार्टी के दायरे से बांधकर देखना उचित नहीं। इस पीढ़ी को आखिर जोड़ता क्या है? इसका जवाब है डिजिटल दुनिया से इसका गहरा जुड़ाव। यह भारत की पहली पीढ़ी है जो स्मार्टफोन और इंटरनेट मीडिया के साथ बड़ी हुई है, जहां खबर पलक झपकते फैल जाती है। इसी वजह से आज कोई भी छोटी नाराजगी देश भर के आक्रोश का कारण बन सकती है।

न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर के युवाओं में इस समय एक बैचनरी दिखाई पड़ती है। उन्हें अपना भविष्य अनिश्चित दिख रहा है। तेजी से बदलती तकनीक, आटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियों पर मंडराता खतरा और सता में बैठे लोगों के प्रति गहराता अविश्वास उन्हें परेशान कर रहा है। पिछले दो वर्षों में नेपाल, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मोरक्को और पेरू जैसे देशों में युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों ने सरकारों को हिला दिया था गिरा भी दिया। इन सभी आंदोलनों में यही एक समान पहलू था कि यह कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, चंद लोगों की चांदी



और नीतियों से स्वयं को बाहर रखे जाने के खिलाफ गुस्सा था। भारत का युवा भी अपने फोन की स्क्रीन पर यह सब देखता है। इसलिए यह असंतोष अब सीमाओं के आरपार महसूस होने लगा है। अपने देश में देखें तो यह बैचनरी पढ़ाई और नौकरी के बीच बढ़ती दूरी से भी पैदा होती है। एक पूरी पीढ़ी को छेढ़ा करने देkhना होगा। बेंगलुरु के किसी स्टार्टअप में काम करने वाला युवक, प्रयागराज में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही छात्रा और किसी छोटे शहर में पारिवारिक काम-धंधा सभाल रहा लड़का, सभी जेन-जी के प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनकी पसंद और प्राथमिकताएं भिन्नता लिए हो सकती हैं। इस पीढ़ी को किसी एक विचारधारा या किसी एक पार्टी के दायरे से बांधकर देखना उचित नहीं। इस पीढ़ी को आखिर जोड़ता क्या है? इसका जवाब है डिजिटल दुनिया से इसका गहरा जुड़ाव। यह भारत की पहली पीढ़ी है जो स्मार्टफोन और इंटरनेट मीडिया के साथ बड़ी हुई है, जहां खबर पलक झपकते फैल जाती है। इसी वजह से आज कोई भी छोटी नाराजगी देश भर के आक्रोश का कारण बन सकती है।

भी तभी मायने रखती है जब युवाओं को सिर्फ प्रचार में चेहरा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि नीति बनाने, संगठन चलाने और फैसले लेने के मोर्चे पर समायोजित किया जाए।

राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में भारतीय परंपरा भी खासी समृद्ध रही है। आचार्य चाणक्य ने राजर्षि की बात कही थी। अर्थात् एक ऐसा शासक जो सत्ता का उपयोग निजी लाभ के लिए नहीं, बल्कि जनता की भलाई के लिए करता है? जो खुद अनुशासन में रहता है और जिसकी असली ताकत जनता के भरोसे से आती है, न कि सिर्फ पद से। राजर्षि की संकल्पना सत्ता को सेवा मानती है। इसमें जनता की नब्ब को समझा जाता है। दंभ से मुक्त होकर आलोचना को गले लगाना पड़ता है। इसमें तात्कालिक लोकप्रियता से अधिक विरासत के निर्माण को महत्व दिया जाता है। जेन-जी के परिप्रेक्ष्य में यह संकल्पना बहुत सार्थक लगती है। इस पीढ़ी को न लंबे भाषण चाहिए और न अनावश्यक प्रचार या मार्केटिंग। उसे ऐसा नेतृत्व चाहिए, जो सत्ता को अपना हक नहीं, अपितु दायित्व समझे। जो फैसला लेने से पहले सुनना सत्ता को सेवा मानती है। जो व्यक्ति से अधिक संस्थाओं को वरीयता दे और जो युवाओं को हाशिए पर नहीं, बल्कि मुख्यधारा का हिस्सा बनाए। राजर्षि की यह संकल्पना हमें यही सिखाती है कि असली और टिकाऊ भरोसा प्रचार से नहीं, बल्कि विनम्रता और जिम्मेदार शासन से ही कमाया जाता है। भारत में जेन-जी की आकांक्षाएं किसी एक चुनाव या एक अभियान की बात नहीं हैं। यह भारत के लोकतंत्र के आने वाले काल की दिशा तय करने वाला सवाल है। जो भी नेतृत्व राजर्षि की संकल्पना को आत्मसात कर उसके अनुरूप आचरण करेगा, वही इस पीढ़ी का भरोसा जीत पाएगा।

कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के हों प्रयास

हरीश पाराशर

ताजा आंकड़ों के मुताबिक 30 अगस्त तक देश में 597.6 मिलिमीटर बारिश हुई है जबकि यह 693.9 मिमी होनी चाहिए थी। हालांकि कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बरसात भी देखी गई है। मोटे अनुमान के अनुसार कुछ राज्यों में अतिवृष्टि को छोड़ दें तो सितंबर में भी सामान्य से कम बरसात होने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। बरसात को लेकर अब अनुमान चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि मानसून आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण आय, उपभोग, रोजगार और खाद्य सुरक्षा का बड़ा आधार कृषि ही है। इस बार भी कहीं कम वर्षा से खरीफ की बुवाई प्रभावित हुई है तो कहीं अत्यधिक वर्षा ने आपदा का रूप लिया है। बुवाई घटने का सीधा असर पैदावार पर पड़ने वाला है और जाहिर है इस वजह से महंगाई की मार और पड़ेगी। दक्षिण-पश्चिम मानसून के अंतिम दौर में देश के 14 राज्यों में सामान्य से कम बरसात से कृषि उत्पादन का संतुलन बिगड़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है। जाहिर है इसका असर खाद्य आपूर्ति और मूल्य स्थिरता दोनों पर पड़ने के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही देश के अधिकांश हिस्सों में औसत से कम बरसत का अनुमान लगाया था। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 30 अगस्त तक देश में 597.6 मिलिमीटर बारिश हुई है जबकि यहाँ 693.9 मिमी होनी चाहिए थी। हालांकि कुछ इलाकों में सामान्य से अधिक बरसात भी देखी गई है। मोटे अनुमान के अनुसार कुछ राज्यों में अतिवृष्टि को छोड़ दें तो सितंबर में भी सामान्य से कम बरसात होने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। बरसात को लेकर यह अनुमान चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि मानसून आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ग्रामीण आय, उपभोग, रोजगार और खाद्य सुरक्षा का बड़ा आधार कृषि ही है। इस बार भी कहीं कम वर्षा से खरीफ की बुवाई प्रभावित हुई है तो कहीं अत्यधिक वर्षा ने आपदा का रूप लिया है। बुवाई घटने का सीधा असर पैदावार पर पड़ने वाला है और जाहिर है इस वजह से महंगाई की मार और पड़ेगी। खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का सीधा असर परिवारों के बजट पर पड़ता है। चिंताजनक तथ्य यह भी है कि जिस अवधि में मानसून को सबसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था, उस अवधि में वह कमजोर रहा है। अहम बात यह है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान में सितंबर तक मानसून में किसी बड़े सुधार के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बारिश की कमी की भरपाई हो पाएगी, इसकी उम्मीद कम ही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान यही कहता है कि मानसून सीजन के बाकी हिस्से में बारिश का प्रदर्शन क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग रह सकता है। कुछ इलाकों में अच्छे बारिश हो ही सकती है। बरसात के पैटर्न में आए इस बदलाव की वजह अल नीनो को माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अस्सर से तापमान भी बढ़ता है। फसलों पर दोहरा असर इन्हीं कारणों से पड़ता है। पैदावार में कमी का असर किसानों की आमदनी पर पड़ता है। ऐसे में कर्ज के बोझ में दबना उनकी मजबूरी हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के पैटर्न में आए इस बदलाव को सितंबर तक मानसून में किसी बड़े सुधार के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। मौसम तंत्र में आ रहे बदलाव की बड़ी वजह भी इनसे जुड़ी है। ऐसे में जरूरत वर्षा पर निर्भरता घटाने की तो है ही, किसानों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रखने वाली नीतियां भी बनानी होंगी। मानसून की अस्थिरता से बार-बार झटके खाती जा रही भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की भी जरूरत है। सिंचाई की वैकल्पिक व्यवस्था, भंडारण के पुख्ता इंतजाम और कृषि में तकनीकी नवाचार नहीं किए गए तो हर वर्ष महंगाई का दबाव तो बढ़ेगा ही, किसानों की आय में भी अस्थिरता का दौर बना रहेगा।

सार-समाचार

पंचायत मंत्री पवार ने जताया

मुख्यमंत्री का आधार

चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि संत गुरु रविदास जी महाराज किसी एक जाति, वर्ग या समाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे पूरी मानवता के महान संत और प्रेरणास्रोत हैं। उनकी शिक्षाएं सामाजिक समरसता, समानता, भाईचारे और मानव सेवा का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी द्वारा संत गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को भव्य रूप से मनाने का प्रस्ताव सदन में रखा गया है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी तथा प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। विकास एवं पंचायत मंत्री आज हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा सदन में लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि संत गुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीर दास जी सहित महान संतों की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। उन्होंने कहा कि जब समाज में छुआछूत और भेदभाव चरम पर था, तब संत गुरु रविदास जी महाराज ने लोगों को समानता और भाईचारे का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि संतों और गुरुओं ने सदैव समाज को अधिकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया है। संत गुरु रविदास जी, संत कबीर दास जी और अन्य महान संतों की वाणी आज भी समाज को एकजुट रहने और मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से ही विभिन्न संतों और महापुरुषों की जयंती सरकारी स्तर पर मनाने की मांग समय-समय पर उठती रही, लेकिन इस दिशा में अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया। वर्ष 2014 में जब श्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, उस समय फरीदाबाद में हुई बैठक में अनुसूचित समाज के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे संत गुरु रविदास जी, गुरु वाल्मीकि जी, संत कबीर दास जी और डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती सरकारी स्तर पर मनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने इस मांग को स्वीकार करते हुए सभी संतों और महापुरुषों की जयंती सरकारी स्तर पर मनाने की प्रक्रिया शुरू की। कलश यात्रा पर विधायक गीता भुक्कल के स्वांग का जवाब देते हुए श्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि संत गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 30 जून को वाराणसी से कलश यात्रा शुरू हुई थी, जिसमें 27 राज्यों के जनप्रतिनिधियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। यह यात्रा देश के 27 राज्यों से होकर गुजरेगी और हरियाणा भी इसका महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पहुंचने पर गुरुग्राम में शर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गुरुग्राम शहर में विभिन्न समाजों और संस्थाओं ने अलग-अलग स्थानों पर स्वागत द्वार बनाकर यात्रा का अभिनंदन किया।

प्रदेश के 118 राजकीय स्कूलों के बनाए

जाएंगे बेहतरीन भवन : शिक्षा मंत्री ढांडा

चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने कहा कि प्रदेश सरकार राजकीय सरकारी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सरकार प्रदेश में 118 राजकीय प्राइमरी मिडिल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के शानदार भवन बनाए जाएंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। सरकार ने सर्वे करवाया था, जिसमें 118 स्कूलों के भवन नहीं थे। उन्हें स्कूलों में आधुनिक भवन बनाए जाएंगे। ताकि विद्यार्थी और बेहतर ढंग से शिक्षा ग्रहण कर सकें। मंत्री हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सुदृढ़ करने तथा यह सुनिश्चित करने बारे लगातार प्रयासरत है कि सभी राजकीय विद्यालयों में छात्र-संख्या अनुसार सुरक्षित एवं पर्याप्त भवन, पेयजल, शौचालय तथा बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं, प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी अन्य आवश्यक सुविधाएं विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समग्रबद्ध तरीके से राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने एवं बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में मरम्मत एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में देरी न हो इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 17 जुलाई 2026 को संबंधित अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में विद्यालयों के कक्षाों की मरम्मत तथा कंडम सामग्री की नीलामी के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इसके अलावा 1,00,000 रुपये तक के बुनियादी ढांचे के माइनर सिविल वर्क के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को तथा 25,00,000 रुपये तक के बुनियादी ढांचे के माइनर सिविल वर्क हेतु संबंधित अतिरिक्त उपायुक्त को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ

गुरुग्राम। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को अब आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलेगा। इससे पहले उन्हें सरकार की आठ सेवाओं का लाभ मिल रहा है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निर्देश पर सभी शहरी स्थानीय निकायों में लोक कल्याण मेला एक सितंबर से शुरू हो गया है और 30 सितंबर तक चलेगा। मंगलवार को लोक कल्याण मेले का आयोजन निगम के पुराने कार्यालय और एसबीआई महरोली रोड पर हुआ। मेले में लंबित ऋणा आवेदनों के निस्तारण, स्वीकृत लेकिन वितरित नहीं हुए ऋण के वितरण और नए ऋणा आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने पर कार्य किया गया। डिजिटल रूप से सक्रिय नहीं हुए लाभार्थियों को यूपीआई और वयूआर कोड से जोड़ा जा रहा है। सिटी प्रोजेक्ट अधिकारी द्वारा प्रसाद ने बताया कि विक्रेताओं को पीएम स्वनिधि मोबाइल एप की जानकारी और डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे ऋण की अदायगी कर चुके पात्र रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। सिटी प्रोजेक्ट अधिकारी ने बताया कि बैंकों की ओर से शिविरों में मौजूद रहकर विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान, लंबित ऋण का वितरण और नए आवेदनों को स्वीकृति देने में सहयोग किया जा रहा है। डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन और यूपीआई प्रक्रियण, वयूआर कोड सक्रिय करने और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के संबंध में जागरूकता लाई जा रही है। जिले में करीब 55 हजार रेहड़ी-पटरी वाले पंजीकृत हैं।

संत – महापुरुषों की शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणास्रोत

गुरु रविदास जी समरसता संकल्प अभियान से संबंधित गठित

कमेटी में विपक्ष के सदस्यों को भी किया जाएगा शामिल: मुख्यमंत्री

चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संत सभी के हैं और हम सभी संतों के हैं। संत-महापुरुषों की शिक्षाएं किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण समाज और मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी भावना के अनुरूप 'गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान' के लिए गठित कमेटी में विपक्ष के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा में 'संत शिरोमणि गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान' पर पेश किए गए सरकारी संकल्प पर चर्चा के दौरान विधायक श्री बी.बी. बत्रा द्वारा कमेटी में विपक्ष को प्रतिनिधित्व दिए जाने का विषय उठाए जाने पर सदन में जवाब दे रहे थे। इस दौरान श्री नायब सिंह सैनी ने गुरु श्री तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस से जुड़े कार्यक्रमों का उल्लेख

करते हुए कहा कि इस महान सदन में गुरु श्री तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के अवसर पर प्रस्ताव लाया गया था और कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कमेटियां भी गठित की गई थीं। इन कमेटियों में विपक्ष के सदस्यों को भी शामिल किया गया था। संबंधित उपायुक्तों द्वारा प्रत्येक स्थान पर विपक्ष के विधायकों को कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया था, लेकिन विपक्ष का एक भी साथी इन कार्यक्रमों में शामिल होता दिखाई नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने इस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वे बड़े भारी मन से सदन में यह बात रख रहे हैं कि गुरु श्री तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर से जुड़े कार्यक्रमों के लिए कमेटियां गठित किए जाने और सभी को आमंत्रित किए जाने के बावजूद विपक्ष की भागीदारी देखने को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी



वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी—

सरकारें जाएंगी, लेकिन यह देश रहना चाहिए। यही संदेश हमारे गुरुओं ने भी दिया है। इस संदेश को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। भावी पीढ़ी को यह पता होना चाहिए कि हमारे संतों और गुरुओं ने समाज एवं मानवता के लिए किस प्रकार के कष्ट सहें और अपना जीवन समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस पवित्र भूमि पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश हुआ है, वहां की मिट्टी घर-घर तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए 'संत शिरोमणि गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान' को राजनीति से ऊपर उठकर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब ऐसे महान संतों और महापुरुषों के प्रकाश पर्व अथवा स्मृति दिवस आते हैं, तो हम सभी को मिलकर आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सदन

में लाया गया सरकारी संकल्प परम श्रद्धेय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व से संबंधित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का ध्येय संत-महापुरुषों का मान-सम्मान करना तथा उनकी शिक्षाओं और संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुओं की वाणी हमें यह संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों के कारण छोटा या बड़ा होता है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि अन्य सभी बातों को पीछे छोड़कर मिलकर इस संकल्प को आगे बढ़ाएं और संत-महापुरुषों की शिक्षाओं को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करें। मुख्यमंत्री ने 'श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान' के तहत आयोजित किए जा रहे।

विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी

को मिलेगी सेवा सुरक्षा : ढांडा

चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने विश्वविद्यालयों के अतिथि प्राध्यापकों (गेस्ट फैकल्टी) के हित में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि सरकार अब कॉलेजों की तर्ज पर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों को भी सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए नया सेवा सुरक्षा अधिनियम 2026 लाने जा रही है। हरियाणा यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्टुअल टीचर एसोसिएशन और हरियाणा यूनिवर्सिटी



मिल चुका है। अब इसी तर्ज पर विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिए 2026 का नया अधिनियम लाया जा रहा है। एमडीयू के कुलपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित 6 प्रमुख मापदंड तय किए हैं। शिक्षक ने 30 जून 2023 तक सहायक प्रोफेसर पर के लिए निर्धारित सभी आवश्यक पात्रता शर्तें पूरी कर ली हों। शिक्षा मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस नए अधिनियम से विश्वविद्यालयों में वर्षों से किया जा चुका है, जिसके तहत 2,095 कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का लाभ

हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के अंतिम

दिन 11 विधेयक चर्चा उपरांत किए गए पारित

चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन 11 विधेयक चर्चा उपरांत पारित किये गये। पारित किए गए विधेयकों में हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026, हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026, हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026, हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा विधेयक, 2026, हरियाणा निजी वि श्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा राज्य महिला आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026, हरियाणा राज्य भौतिक चिकित्सा परिषद्

(निरसन) विधेयक, 2026, हरियाणा विधि अधिकारी (विनियोजन) संशोधन विधेयक, 2026 तथा हरियाणा कारबार का अधिकार अधिनियम,2026 शामिल हैं। मार्च, 2027 के इकतीसवें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 7136,63,25,000 रुपये (केवल सात हजार एक सौ छत्तीस करोड़, तिरसठ लाख, पच्चीस हजार रुपये) के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2026 पारित किया गया है। हरियाणा राज्य में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण तथा रक्षणियों, धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों की अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक,

शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक अपेक्षाओं के बारे में अनुसंधान करने, धर्म-निरपेक्ष परम्पराओं का परिचरण करने और राष्ट्रीय एकीकरण को बलवाने के उद्देश्य से तथा उससे सम्बन्धित या उससे अनुपूरणिक मामलों के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन करने हेतु हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2026 पारित किया गया। हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राज्य स्तर पर एक संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है, ताकि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए संविधान तथा विधियों में प्रदत्त सुरक्षा उपायों का मूल्यांकन किया जा सके और हरियाणा राज्य में ऐसे सुरक्षा उपायों तथा विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिफारिशों की जा सकें।

दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में जमकर हुई बारिश

दिल्ली, समय जगत। दिल्ली-एनसीआर में बुधवार को मौसम ने एक बार फिर करवट बदली। फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के वसंत कुंज समेत कई इलाकों में भी बारिश से मौसम सुहावना हो गया। हालांकि, बारिश के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और कई जगहों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। दिल्ली में मानसून का पैटर्न पिछले तीन साल में तेजी से बदल है। अब जून में ग्री-मानसून बारिश कमजोर रह रही है, जबकि जुलाई और अगस्त में कम अवधि के दौरान तेज बारिश के स्पेल बढ़ रहे हैं। वर्ष 2023 में जुलाई में रिकॉर्ड बारिश के बाद अगस्त सूखा



रहा था, लेकिन 2024 से जुलाई-अगस्त दोनों महीनों में लगातार सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो रही है। इस साल 26 अगस्त तक इन दोनों महीनों में करीब 612 मिमी बारिश हो चुकी है। दिल्ली में मानसून के आमन की सामान्य तारीख 29 जून है। इस

जुलाई में 507.1 मिमी बारिश हुई थी, जो सामान्य से 141 प्रतिशत अधिक थी और 2003 के बाद जुलाई की सबसे ज्यादा बारिश थी। इसके विपरीत अगस्त में महज 91.8 मिमी बारिश हुई। इसके बाद 2024 से बारिश का वितरण बदला। जुलाई लगभग सामान्य रहा, लेकिन अगस्त में 390.3 मिमी बारिश हुई। 2025 में जुलाई और अगस्त दोनों में अधिक बारिश हुई और अगस्त में 400.1 मिमी पानी बारसा, जो 15 साल में इस महीने का सर्वाधिक आंकड़ा था। 2026 में भी यही प्रवृत्ति जारी है। चार से आठ अगस्त के बीच पांच दिन में 224.7 मिमी बारिश हुई, जबकि 25 अगस्त को 24 घंटे में 99.1 मिमी बारिश दर्ज की गई।

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के

समापन पर मुख्यमंत्री ने की प्रेस वार्ता

चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिकारों के साथ मर्यादा और जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। विरोध के नाम पर नियम तोड़ना अथवा सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। किसी कर्मचारी पर अपना राजनीतिक गुस्सा निकालना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यह बात हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के समापन अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि तीन दिन चले इस सत्र में तीन बैठकें हुईं और लगभग 16 घंटे सकारात्मक एवं सार्थक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने सत्र को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त



किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा की अपनी गरिमा, परंपराएं और सुरक्षा संबंधी नियम हैं। यदि किसी व्यवस्था के तहत नारे लखी तख्तियां लेकर विधानसभा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है कि वह उस व्यवस्था का पालन करें। केवल विधायक होने का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति नियम और कानून

से ऊपर हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकारी भी हैरानी हुई कि कुछ कांग्रेस विधायक विरोध प्रदर्शन को विधानसभा के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की तक ले गए और इस घटनाक्रम में नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि श्री हुड्डा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं और आज नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ नेता से संयम और मर्यादा की अपेक्षा स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के पास मुद्दों का घोर अभाव है और मुद्दा विहीन कांग्रेस जिस गति से झूट फैलाती है उस गति से तो हवा भी नहीं चलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीतियों व योजनाओं के कारण आज भारत के विकास की चर्चा भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर भी हो रही है।

‘गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान’

का मुख्यमंत्री ने पेश किया सरकारी प्रस्ताव

चंडीगढ़, समय जगत। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित देशव्यापी 'गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान' के संबंध में सरकारी प्रस्ताव पेश किया और सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि गत 29 जुलाई, 2026 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शुरू हुआ यह अभियान 20 फरवरी, 2027 तक चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के समता, ममता, करुणा, सेवा, भक्ति, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समरसता के संदेश को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना तथा विभिन्न वर्गों में सामाजिक एकता को और मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान का शुभारंभ संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी से हुआ। इस

अवसर पर वहां की पवित्र मिट्टी से भरे कलश का पूजन कर उन्हें देशभर के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंपा गया। हरियाणा में श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित कलश यात्रा 4 अगस्त, 2026 को पहुंची तथा इसके स्वागत में 5 अगस्त, 2026 को गुरुग्राम स्थित माता शीतला मंदिर परिसर में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इसमें लाए गए कलशों को जिला एवं ग्राम स्तर तक पहुंचाया जा रहा है, जहां श्रद्धालु पावन मिट्टी को स्थानीय मंदिरों की मिट्टी में मिलाकर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के सामाजिक समरसता के संदेश को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि समरसता यात्रा आगामी 5 अक्टूबर को हरियाणा में पहुंचेगी और 5 नवंबर, 2026 तक चलेगी। यात्रा के स्वागत के लिए इसके मार्ग में पूरे प्रदेश में प्रवेश द्वार और स्वागत स्थल तैयार किए जाएंगे तथा जनसभाएं आयोजित की जाएंगी।

स्वदेशी के संकल्प के साथ लखनऊ रवाना होंगे महोबा के व्यापारी, महाकुंभ में दिखेगी एकजुटता

राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संपन्न हुई महत्वपूर्ण बैठक

महोबा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में लखनऊ में आयोजित होने वाले स्वदेशी व्यापारी महाकुंभ को लेकर महोबा में बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिलाध्यक्ष स्वप्निल गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में महाकुंभ में महोबा जनपद की प्रभावी एवं गरिमामयी सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि महोबा जनपद से लगभग एक सैकड़ व्यापारी लखनऊ पहुंचकर स्वदेशी व्यापारी महाकुंभ में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम को लेकर व्यापारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। बैठक में अधिक से अधिक व्यापारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा लखनऊ पहुंचने की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान व्यापारियों ने 'विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ' के संदेश को जन-जन तक



पहुंचाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाना केवल व्यापार का विषय नहीं, बल्कि देश के कारीगरों, लघु उद्यमियों, स्थानीय व्यापारियों और बाजारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

जिलाध्यक्ष स्वप्निल गुप्ता ने कहा कि महोबा के व्यापारी एकजुट होकर लखनऊ पहुंचेंगे और स्वदेशी अभियान को मजबूती प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। बैठक में संगठन के

पदाधिकारियों एवं व्यापारी साथियों ने महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। व्यापारियों ने कहा कि महोबा की धरती से लखनऊ पहुंचने वाला व्यापारी वर्ग स्वदेशी, स्थानीय व्यापार और आत्मनिर्भर भारत का मजबूत संदेश देगा।

महोबा पुलिस बनी प्रदेश में नंबर 1, आईजी आरएस में मिले 100 प्रतिशत अंक

अगस्त की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद महोबा ने त्वरित निराकरण और तकनीकी दक्षता का नया मानक किया स्थापित

महोबा। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा माह अगस्त 2026 के आंकड़ों के आधार पर जारी प्रदेश स्तरीय आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) रैंकिंग में जनपद महोबा पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। महोबा पुलिस को पूरे प्रदेश में 100 प्रतिशत अंक मिले हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि जनपद के प्रत्येक थाने ने भी 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। यह उपलब्धि पूरे जनपद की एकजुट टीम वर्क और सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली को दर्शाती है।

यह सफलता पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह, के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्राप्त हुई है। दोनों अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना स्तर से लेकर जनपद स्तर तक शिकायतों के त्वरित निस्तारण, नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त नागरिक



शिकायतों का शीघ्र निपटारा, ऑनलाइन निगरानी, समयबद्ध अनुपालन और तकनीकी प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग इस रैंकिंग का आधार बना। जनपद पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित न रहे तथा प्रत्येक प्रकरण का निस्तारण निर्धारित समय-सीमा में हो।

पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि महोबा पुलिस की पूरी टीम की लगन, अनुशासन और आम नागरिकों के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों, कर्मियों और पर्यवेक्षण अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि लक्ष्य केवल रैंकिंग में शीर्ष पर रहना नहीं, बल्कि नागरिकों को शीघ्र और संतोषजनक न्याय उपलब्ध कराना है। आईजीआरएस को और अधिक प्रभावी बनाने तथा शून्य लंबित शिकायतों की स्थिति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक महोबा के कुशल नेतृत्व में थानावार समीक्षा, नियमित अनुश्रवण और फील्ड स्तर पर मार्गदर्शन से यह परिणाम संभव हो सका। जनपद पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी शिकायत के लिए आईजीआरएस पोर्टल तथा निर्धारित पुलिस हेल्पलाइन का उपयोग करें। जन सहयोग से ही इस व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकेगा।

UPCOS के शुभारंभ पर कीर्त सागर में आयोजित हुआ सम्मान समारोह उत्कृष्ट आउटसोर्स कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए



महोबा । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं डिजिटल एकीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के शुभारंभ के अवसर पर आज कीर्त सागर, नट पर स्थित संस्कृतिक मंच में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण एवं सम्मान समारोह

आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोबा श्रीमती गजल भारद्वाज, नगरपालिका चेयरमैन डॉ संतोष चौरसिया सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के उद्बोधन का सजीव

प्रसारण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा, पारदर्शी व्यवस्था, समयबद्ध मानदेय भुगतान तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। PCOS के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाएगा तथा अनावश्यक बिचौलियापन एवं शोषण की संभावनाओं को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मि प्रदेश के विकास एवं जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक कार्मिक को उसके अधिकार, सम्मान एवं सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों का हुआ सम्मान: समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने

वाले आउटसोर्स कार्यकर्ताओं एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि UPCOS का गठन आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों को उनके अधिकार, सम्मान एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। सफाई कर्मी एवं अन्य जमीनी स्तर के कर्मचारी प्रतिदिन महत्वपूर्ण जनसेवा का कार्य करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है।

पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध : जिलाधिकारी-समारोह के समापन पर जिलाधिकारी श्रीमती गजल भारद्वाज ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों,

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी एवं व्यवस्थित मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था लागू करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी ने सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए शुभकामनाएं देते हुए कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन करने पर बल दिया। कार्यक्रम में जिला पंचायती राज अधिकारी सी. के. चर्मा, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका अवधेश कुमार, सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, नगरपालिका के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी उपस्थित रहे।

साक्षित समाचार

ग्राम शिवनी में बाढ़ पीड़ित परिवारों को वितरित की गई राहत सामग्री



समय जगत मौदहा/ हमीरपुर। बाढ़ प्रभावित ग्राम शिवनी में सोमवार को बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री एवं आवश्यक किट का वितरण किया गया। राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि देववर्चन यादव की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी हमीरपुर, उपजिलाधिकारी मौदहा, लेखपाल तथा थाना प्रभारी मुस्करा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में बाढ़ प्रभावित परिवारों को आवश्यक सामग्री की किट प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान प्रधान प्रतिनिधि देववर्चन यादव ने उपस्थित उच्च अधिकारियों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों की सहायता एवं राहत कार्यों में सहयोग के लिए अधिकारियों और ग्राम प्रतिनिधि के प्रयासों की सराहना की गई। ग्रामीणों ने राहत एवं सहयोग कार्य के लिए प्रशासन और ग्राम प्रतिनिधि के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनसेवा ही सच्ची सेवा है।

कांग्रेस की पुरानी यादें हुई ताज़ा, वरिष्ठ कांग्रेसी से आत्मीय मुलाकात
बांदा आज का दिन कांग्रेस परिवार के लिए बहुत ही भावनात्मक और यादगार रहा। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश दीक्षित जी एवं महिला जिला अध्यक्ष आदरणीय सीमा खान जी ने वरिष्ठ एवं पुरानी कांग्रेसी, डॉ. विक्रम सिंह जी की माताजी आदरणीय श्रीमती राजरानी जी के निवास पर पहुंचकर उनसे आत्मीय मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पुराने दिनों, संघर्षों, आंदोलनों और संगठन की गौरवशाली परंपराओं को याद करते हुए पुरानी यादें ताज़ा की गईं। वरिष्ठ कांग्रेसियों के अनुभवों और उनके द्वारा पार्टी के लिए किए गए संघर्षों को याद कर कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास की अनेक यादें फिर से जीवंत हो उठीं। डॉ. विक्रम सिंह जी की माताजी आदरणीय राजरानी जी ने अपने समय की कांग्रेस और पार्टी से जुड़ी अनेक पुरानी एवं यादगार बातें साझा कीं। उनकी बातों और अनुभवों ने सभी को कांग्रेस के गौरवशाली अतीत की याद दिला दी। वरिष्ठ साथियों का अनुभव, उनका संघर्ष और पार्टी के प्रति उनका समर्पण हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक अमूल्य धरोहर है। कांग्रेस पार्टी की मजबूत नींव ऐसे ही वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष और समर्पण से बनी है। यह मुलाकात केवल एक सामान्य भेंट नहीं थी, बल्कि कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास, पुरानी परंपराओं और अपने वरिष्ठ साथियों के सम्मान को समर्पित एक भावनात्मक अवसर था।

मध्यस्थता अभियान- 3.0 को मिल रहा सकारात्मक

प्रतिसाद, पक्षकार बढ़-चढ़कर उठा रहे लाभ

समय जगत हमीरपुर। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर श्री मनोज कुमार राय के मार्गदर्शन तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती वंदना अग्रवाल के निर्देशन में मध्यस्थता अभियान- 3.0 के अंतर्गत उपयुक्त वादों का मध्यस्थता के माध्यम से सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 02 सितम्बर 2026 को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) न्यायालय में लंबित एक दीवानी वाद, जिसमें नगर पालिका राट एक पक्षकार थी, को एडीआर सेंटर में मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया गया। मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक सुलह-समझौता कराया गया। इसी प्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में लंबित परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित एक वाद का भी मध्यस्थता के माध्यम से सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया। इसके अतिरिक्त धारा 323 एवं 504 भारतीय दंड संहिता से संबंधित एक आपराधिक मामले तथा पति-पत्नी के मध्य लंबित एक वैवाहिक मामले का भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर सफलतापूर्वक निस्तारण कराया गया।

इन मामलों का सफल निस्तारण इस बात को दर्शाता है कि संवाद, सहमति एवं सहयोग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विवादों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है। मध्यस्थता पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान अपने विवाद का समाधान आपसी सहमति से प्राप्त करने का प्रभावी अवसर प्रदान करती है।

इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती वंदना अग्रवाल ने सफलतापूर्वक समझौता करने वाले दोनों पक्षकारों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों से अपील की कि अधिकाधिक उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता हेतु संदर्भित कराएं तथा मध्यस्थता की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान करें, जिससे मध्यस्थता अभियान-3.0 को सफल एवं प्रभावी बनाया जा सके।

यूपीसीओएस के शुभारंभ पर कलेक्टर सभागार में आयोजित हुआ सम्मान समारोह

समय जगत हमीरपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स मानव संसाधन प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं डिजिटल एकीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गठित उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के शुभारंभ के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट सभागार, हमीरपुर में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माननीय विधायक सदर डॉ. मनोज कुमार प्रजापति, जिलाधिकारी हमीरपुर श्री अभिषेक गोयल, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती शकुन्तला निषाद तथा नगरपालिका चेयरमैन श्री कुलदीप निषाद सहित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने सहभागिता की।

कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के उद्बोधन का सजीव प्रसारण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा, पारदर्शी व्यवस्था, समयबद्ध मानदेय भुगतान तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित



करने के लिए प्रतिबद्ध है। UPCOS के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के मानव संसाधन प्रबंधन को डिजिटल एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जाएगा तथा अनावश्यक बिचौलियापन एवं शोषण की संभावनाओं को समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मि प्रदेश के विकास एवं जनसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य प्रत्येक कार्मिक को उसके अधिकार, सम्मान एवं सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आउटसोर्स कार्यकर्ताओं एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं नगर पालिका के सफाई कर्मियों को

कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सेफ्टी जैकेट, सुरक्षा किट एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर माननीय विधायक सदर डॉ. मनोज कुमार प्रजापति ने कहा कि UPCOS का गठन आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों को उनके अधिकार, सम्मान एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। सफाई कर्मी एवं अन्य जमीनी स्तर के कर्मचारी प्रतिदिन महत्वपूर्ण जनसेवा का कार्य करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा एवं गरिमा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। समारोह के समापन पर जिलाधिकारी श्री अभिषेक गोयल ने उपस्थित

जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा PCOS पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी एवं व्यवस्थित मानव संसाधन प्रबंधन व्यवस्था लागू करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिलाधिकारी ने कहा कि सफाई कर्मियों को वितरित किए गए सेफ्टी जैकेट एवं सुरक्षा किट उनके कार्य के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक होंगे। उन्होंने सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए शुभकामनाएं देते हुए कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन करने पर बल दिया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी न्यायिक रिजवाना शाहिद, डिप्टी कलेक्टर पैगाम हैदर, सूचना अधिकारी सतीश कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, नगरपालिका के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी उपस्थित रहे।

भागवत कथा के दूसरे दिन शुक्रदेव जन्म और अमर कथा का हुआ वर्णन



पार्वती जी को सुनाई गई अमर कथा और राजा परीक्षित को शुक्रदेव जी द्वारा भागवत कथा सुनाने के प्रसंग का वर्णन किया। आचार्य जी ने बताया कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से अमर होने की कथा सुनाने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाई, जिसे शुक्र रूप में बैठे शुक्रदेव जी ने भी सुन लिया और वे अमर हो गए। बाद में वही शुक्रदेव जी महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित को श्री गुरु ऋषि के श्राप के कारण सात दिन में तक्षक नाग द्वारा मृत्यु का श्राप मिला था। मोक्ष की कामना से राजा परीक्षित ने शुक्रदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनी और मुक्ति को प्राप्त हुए। भागवत सुनने से ही जीव का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ एवं पूजन अर्चन पंडित दिवाकर शुक्ला एवं परमानंद त्रिपाठी द्वारा किया गया। इस दौरान सिंगर रोहित सिंह एवं तबला वादक कुलदीप त्रिपाठी ने अपने सुमधुर भजनो से पंडाल को भक्तिमय कर दिया। कथा परीक्षित के रूप में श्रीमती लक्ष्मी - शिवम जी ने सपरिवार एवं इष्ट मित्रों के साथ कथा का रसपान किया। कथा के दौरान पूरा पंडाल राधे-राधे के जयकारों से गुंजा उठा और श्रद्धालु भक्ति में झूमते पूजा करते आए।

किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ का मैराथन धरना, अधिकारियों को चेताया

आगरमालवा। किसानों की विभिन्न समस्याओं और विभागीय स्तर पर बरती जा रही कथित लापरवाही के विरोध में भारतीय किसान संघ तहसील आगर मालवा द्वारा पिपलान चौपाटी पर धरना प्रदर्शन किया गया। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक चले धरने में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान किसान नेताओं ने कृषि, राजस्व और मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीरता बरतने की चेतावनी दी। किसान संघ द्वारा कलेक्टर आगर-मालवा के नाम दिए गए ज्ञापन में कृषि एवं

सहकारिता, राजस्व, विद्युत, जल संसाधन तथा बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी कई प्रमुख समस्याओं को उभराया गया है। **फसल बीमा भुगतान में पारदर्शिता की मांग-** किसान संघ ने खरीफ वर्ष 2025-26 में सोयाबीन फसल में हुए नुकसान के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबित दावों का शीघ्र भुगतान करने की मांग की। संघ का आरोप है कि पूर्व में कई बार पत्र एवं ज्ञापन दिए जाने के बावजूद किसानों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। संघ ने धरना स्थल पर जिले की री-ब्रॉफिंग रिपोर्ट उपलब्ध कराने तथा फसल बीमा दावों का पुनः परीक्षण

एवं गणना कराने की मांग रखी।

राजस्व मामलों में देरी पर नाराजगी- किसानों ने बंटवारा, नामांतरण और राजस्व न्यायालयों में लंबे समय से लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। संघ ने कहा कि किसानों को छोटे-छोटे राजस्व कार्यों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ज्ञापन में विधिवत नामांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन करने,



किसानों की विभिन्न समस्याओं के विरोध में भारतीय किसान संघ तहसील आगर मालवा द्वारा पिपलान चौपाटी पर धरना प्रदर्शन किया गया।

सौमांकन प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण और राजस्व न्यायालयों के आदेशों का तत्काल पालन कराने की मांग भी की गई।

बिजली व्यवस्था को लेकर भी

जताया विरोध- धरने में किसानों ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। आगामी खरी सीजन को देखते हुए ट्रांसफर्मरों की पर्याप्त उपलब्धता, ओवरलोड ट्रांसफर्मरों पर लोड कम करने, खराब ट्रांसफर्मरों को

समाधान में अनावश्यक देरी की जा रही है। बकाया बिजली बिल की वसूली के नाम पर किसानों के ट्रांसफर्मर बंद करने की कार्रवाई के बजाय नियमानुसार संबंधित उपभोक्ताओं से ही वसूली करने की मांग रखी गई।

सिंचाई और बैंक संबंधी समस्याएं भी उठाईं- जल संसाधन विभाग के समक्ष आगर तहसील के राजस्व ग्रामों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र में चल रही सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई। वहीं बैंक ऑफ इंडिया सहित बैंकों में किसानों के बचत खातों से अत्यधिक राशि काटे जाने की शिकायत भी ज्ञापन में की गई। किसान

संघ ने मांग की कि पॉजिट किसानों की राशि वापस उनके खातों में जमा कराई जाए। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि किसान लगातार अपनी समस्याओं को लेकर विभागों के अधिकारियों के समक्ष पहुंच रहे हैं, लेकिन कई मामलों में उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अधिकारियों की इस कार्यप्रणाली को अब किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान संघ ने चेतावनी दी कि यदि ज्ञापन में उठाई गई समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण नहीं किया गया तो आगामी दिनों में आंदोलन को और अधिक व्यापक एवं सख्त किया जाएगा।

दो युवकों की मौत, नशे के ओवर डोज की आशंका

सिविल लाइन थाने और कोतवाली थाने का मामला

विदिशा। जिले में अवैध नशे का कारोबार काफी फल फूल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन सख्त कदम न उठा रहा हो, लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुलिस के चाहने के बावजूद भी अवैध नशे के कारोबार पर रोक नहीं लग पा रही है। पिछले 5 महीने में विदिशा नगर में करीब चार-पांच लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही दो मामले नगर में फिर सामने आए हैं। दो लोगों की अवैध नशे का ओवर डोज होने के कारण मौत होने की घटना सामने आई है। जिसमें एक मामला सिटी कोतवाली थाने का है और दूसरा मामला सिविल लाइन थाने के अंतर्गत का है। एक दिन में हुई दो घटनाओं ने कहीं न कहीं लोगों के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है आखिर ऐसा क्या कारण है कि युवा पीढ़ी अवैध नशे में लिप्त होकर भविष्य बर्बाद करने पर तुली हुई है। इस और नगर के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरकर बासोदा जैसा विरोध प्रदर्शन और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा तब कहीं कारगर अवैध नशे के कारोबार पर शिकंसा कसा जा सकता है। शहर में अवैध नशे के कारोबार पर नियंत्रण के पुलिस के प्रयासों के बीच नशे से जुड़ी दो अलग-अलग घटनाओं ने एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुधवार को एक और सिविल लाइन थाना क्षेत्र की तखतमल कॉलोनी के बगीचे में 22 वर्षीय युवक मृत अवस्था में मिला, जिसके हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ था। वहीं दूसरी ओर कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले 19 वर्षीय युवक की भोपाल में मौत हो गई। दोनों मामलों में नशे से जुड़े होने की आशंका सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है।

बगीचे में बेसुध मिला युवक, हाथ में लगा



था इंजेक्शन: सिविल लाइन थाना क्षेत्र की तखतमल कॉलोनी स्थित बगीचे में बुधवार दोपहर करीब 12 बजे एक युवक बेसुध अवस्था में पड़ा मिला। काफी देर तक युवक में कोई हलचल दिखाई नहीं देने पर आसपास के लोगों ने पास जाकर देखा तो उसके बाएं हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ था और उसकी सांसें उखड़ चुकी थीं। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में मृतक की पहचान 22 वर्षीय विकास दांगी निवासी संग्रामपुर, जिला रायसेन के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

दूसरी घटना में 19 वर्षीय युवक की भोपाल में मौत: इसी बीच कोतवाली थाना क्षेत्र के खेड़ापति माता मंदिर के पास गली नंबर-2 निवासी विनोद

रैकवार के 19 वर्षीय बेटे तरुण रैकवार की भोपाल में मौत होने का मामला सामने आया है। बुधवार दोपहर करीब 2 बजे परिजनों ने आरोप लगाया कि घटना से एक दिन पहले तरुण के कुछ साथी उसे अपने साथ लेकर गए थे। परिजनों के अनुसार, उनके साथ रहने वाले युवक पाउडर और इंजेक्शन का नशा करते हैं और वे अपने साथ नशीला पदार्थ भी लेकर गए थे। इसके बाद तरुण की मौत की खबर परिवार को मिली। घटना के बाद परिजनों ने उसके साथ ले जाने वाले युवकों से सख्ती से पूछताछ करने और मामले में कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने आशंका जताई है कि कहीं साथ ले जाने वाले युवकों ने तरुण को भी नशे की गिरफ्त में तो नहीं धकेला था।

दो घटनाओं ने बड़ा चिंता: एक ही दिन सामने आई इन दोनों अलग-अलग घटनाओं में युवाओं की मौत ने शहर में बढ़ते नशे के खतरे को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि दोनों मामलों में मौत के वास्तविक कारण अभी जांच का विषय हैं। पुलिस द्वारा घटनाओं से जुड़े लोगों और परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि दोनों युवकों की मौत के पीछे वास्तविक कारण क्या था।

बासोदा में जागरूकता की पहल, विदिशा में भी जरूरत: पिछले दिनों गंजबासोदा में नशे के खिलाफ साधु-संतों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया था। रैली के माध्यम से युवाओं और उनके परिवारों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया।

नेशनल लोक अदालत के लिए बैठक आयोजित

विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला सचिव हुई शामिल

समय जगत, सिवनी मालवा। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए न्यायालय परिसर में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जिला सचिव न्यायाधीश के. शिवानी, न्यायाधीश सुश्री अंजली अग्रवाल, सुश्री सरोज डेहरिया और अधिवक्तागण उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला विधिक



सेवा प्राधिकरण जिला सचिव न्यायाधीश के. शिवानी ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा बाद प्रकरणों के समाप्त कराने के लिए अधिवक्तागण अपने पक्षकारों को समझाव देकर नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में सहयोग करें। इस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रकरणों में यदि विधिवत तरीके से तामीली हो और अधिक से अधिक पक्षकार उपस्थित होते हैं तो अधिक प्रकरणों में राजीनामा होकर प्रकरण समाप्त हो सकते हैं। इस पर न्यायाधीश सुश्री डेहरिया ने कहा कि इसके लिए आप अपने प्रकरणों की सूची

जिनमें राजीनामा की संभावना है, उन्हें 8 सितंबर के पहले न्यायालय में उपलब्ध कराएं। जिससे जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर प्रकरणों के पक्षकारों को विधिवत तामीली करायी जा सके। न्यायाधीश सुश्री अग्रवाल ने कहा कि यह तीसरी नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को आयोजित हो रही है। जिस तहत आप सभी ने मिलकर पिछली लोक अदालतों को सफल बनाया है। उसी तरह इस नेशनल लोक अदालत में भी पक्षकारों को समझाव देकर अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा करारकर प्रकरणों को समाप्त कराने में सहयोग करें।

उपचुनाव क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन हो- कलेक्टर डॉ. मीना

जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी की बैठक एवं मीडिया ब्रीफिंग सम्पन्न

आगर मालवा। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा जिले में आकस्मिक रूप से रिक हूए पदों के लिए उप निर्वाचन-2026 पूर्वाह्न की घोषणा कर दी गई है। जिले की नगर परिषद सुसनेर के अध्यक्ष का पद वर्तमान में रिक्त है। चूंकि इस बार नगर परिषद अध्यक्ष पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होना है, इसलिए नगर परिषद सुसनेर के सभी 15 वार्डों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, जो 03 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगी। नगर परिषद सुसनेर में 15 वार्ड, कुल 17 मतदान केन्द्र हैं, जिनमें कुल 13843 मतदाता हैं, जिसमें महिला-6928, पुरुष-6914 एवं अन्य में 01 मतदाता हैं। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शेर सिंह मीना ने एवं एसपी दिलीप सोनी की उपस्थिति में जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमेटी बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उप निर्वाचन कार्यक्रम की



विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने प्रतिबंधात्मक आदेश, कोलाहल नियंत्रण आदेश, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग आदि के बारे में बताया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने अवगत करवाया कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 08 सितम्बर 2026 से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जो 15 सितम्बर 2026 को अपराह्न 03.00 बजे तक चलेगी। नाम निर्देशन पत्र लेने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सुसनेर को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसी अनुक्रम में 16 सितम्बर से प्राप्त नाम-निर्देशन पत्रों की जांच (संवेक्षण) होगी एवं 18 सितम्बर 2026 तक अन्त्यर्था अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के तुरंत बाद ही निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार कर प्रतिक चिन्ह रिटर्निंग अधिकारी द्वारा आवंटित किये जायेंगे। प्रतिक चिन्ह आवंटन पश्चात मतपत्र मुद्रण की कार्यवाही नोडल

अधिकारी द्वारा की जायेगी। इसके बाद 29 सितम्बर 2026 दिन-मंगलवार को प्रातः 07.00 बजे से मतदान प्रारंभ होगा, जो अपराह्न 05.00 बजे तक चलेगा। मतदान के बाद 03 अक्टूबर 2026, शनिवार को प्रातः 09.00 बजे से मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा निर्धारित स्थान पर की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों एवं नागरिकों से अपराह्न आचार संहिता का पालन करने तथा निर्वाचन को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करने की अपील की है। बैठक में मीडिया ब्रीफिंग में एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, एसएसपी रविन्द्र बोयत, एसडीएम सुश्री देवकुंवर सोलंकी, एसडीओपी देवनारायण यादव, स्टैंडिंग कमेटी सदस्य अशोक प्रजापत, ईश्वर अजमेरिया, अनमोल वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं पत्रकारागण उपस्थित थे।

सार-समाचार

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय उ.मा.वि. आगर की छात्राओं की समस्याओं का त्वरित समाधान



आगर मालवा। कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय आगर में अध्ययन के लिये निगानिया बैजनाथ से आने वाली छात्राओं की समस्याओं का त्वरित समाधान कर दिया है। कलेक्टर एवं एसपी के निर्देश पर आरटीओ ने निगानिया बैजनाथ रूट से आगर आने वाली बसों के ऑपरेटरों को निर्देशित किया है कि वे प्रप्रिडिन स्कूल आने वाली छात्राओं का निगानिया बैजनाथ से अपनी बसों से बैठाकर आगर तक अनिवार्य रूप से लाएं। सभी बस ऑपरेटरों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूली छात्र-छात्राओं को किराये देने के बावजूद भी बस बैठाते से इंकार न करें, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि निगानिया बैजनाथ की आगर आने वाली छात्राओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना एवं एसपी दिलीप सोनी से भेंटकर उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराया। इस पर कलेक्टर ने तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी और आरटीओ निर्देशित कर छात्राओं की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस पर निगानिया बैजनाथ रूट के सभी बस ऑपरेटरों ने उक्त छात्राओं को बस से आगर लाने की सहमति प्रदान की। अपनी समस्या का त्वरित समाधान पाकर स्कूली छात्र-छात्राएं खुशी-खुशी अपने घर को रवाना हो गईं।

सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित



अशोकनगर। शासन के निर्देशानुसार 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान संचालित किया जायेगा। अभियान के संचालन हेतु कलेक्टर साकेत मालवीय की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में तैयारियों के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार अभियान अंतर्गत गतिविधियां संचालित की जाए। इस हेतु पहले से ही प्लान तैयार रखा जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग समय-समय के साथ अभियान अंतर्गत गतिविधियां आयोजित की जाए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजेश जैन, अपर कलेक्टर दीपनसिंह, संयुक्त कलेक्टर सोमन जैन, विकास कुमार आनंद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

किसान मोर्चा ने मनाई भगवान बलराम जयंती
समय जगत, आगर मालवा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा बुधवार को भगवान बलराम की जिला स्तर पर भाजपा जिला कार्यालय पर जयंती मनाई गई। बलराम जयंती पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बलराम ने अपने हाल से नदियों के मार्ग मोर और धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश किया। कार्यक्रम में किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष जिला दिनेश परमार, विक्रम बोडाना पार्षद, कांस्त सिंह चौहान, तुषार सिंह चौहान, सतोष यादव, सुनील जैन एक्टरसेन, राजेश सिसोदिया एक्टरसेन, राजेश मेवाड़ा दीपक गुप्ता आदि उपस्थित थे।

विदिशा। बुधवार को व्यापार महासंघ के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के नाम आवेदन दिया गया। उन्होंने बताया कि नगर में डीजे संचालकों द्वारा धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में बाजार में जुलूस आदि निकाले जाने पर बहुत ही अधिक तेज आवाज में बजाए जा रहे हैं। जिसके कारण से बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और आम लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य बाजार से सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान डीजे को तेज आवाज में बजाया जाता है। जिससे लोगों के लिए काफी परेशानियां उठनी पड़ती है। लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की निर्देशों का भी पालन नहीं किया जा

रहा है। उन्होंने आवेदन देकर पुलिस अधीक्षक से तेज आवाज में बजने वाले डीजे पर रोक लगाने की मांग की है। व्यापार महासंघ अध्यक्ष राजेश जैन, नरेंद्र सोनी, विवेक शर्मा, आशीष माहेश्वरी ने बताया कि डीजे वाले जलसा, जुलूसों या धार्मिक कार्यक्रमों, यात्राओं में तेज साउंड से डीजे बजाते हैं। इससे सबसे ज्यादा हार्ट के मरीज प्रभावित होते हैं, उनकी जान का भी खतरा बना रहता है। साथ ही बहरेपन एवं कान का पर्दा फटने का डर लग रहता है। वहीं रोड पर जब डीजे बजते हुए निकलता है तब साउंड इतना तेज होता है कि



दुकानों में रखे हुए सामान अपने आप बाइब्रेट होने से गिरने लगते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारी, आम नागरिक, महिलाएं एवं बच्चे सभी डीजे की तेज आवाज से परेशान हैं। उच्चतम न्यायालय के नियमानुसार रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना प्रतिबंधित है और शासन के निर्धारित डेसिबल से अधिक तेज आवाज में नहीं बजाया जा सकता है। बिना

अनुमति के बजने वाले डीजे पर तुरंत कार्यवाही की जाए और निर्धारित सीमा से अधिक आवाज पर बजने वाले डीजे का लाइसेंस निरस्त कर भारी जुर्माना वसूला जाए एवं उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। पूर्व में भी विदिशा व्यापार महासंघ के व्यापारिक संगठनों ने ज्ञापन देकर प्रशासन और पुलिस से तेज आवाज में चल रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कार्यवाही करने का निवेदन किया था, लेकिन लंबे समय से शासन प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अति शीघ्र तेज आवाज में बजने वाले

डीजे पर कानूनी कार्यवाही कर आमजन को राहत प्रदान की जाए। तेज आवाज वाले डीजे पर सख्त कार्यवाही न होने की स्थिति में व्यापार महासंघ कठोर निर्णय लेने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने कहा कि नगर के लोगों को होने वाली परेशानियों की ओर ध्यान देना चाहिए। धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में डीजे को कम आवाज में बजाने दिया जाए। अगर इसके बावजूद भी डीजे अपनी मममर्जी से तेज आवाज में बजता है तो ऐसे डीजे को शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में न लगाया जाए। जिससे लोगों को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापार महासंघ के अन्य सदस्य मौजूद थे।